उत्तराखंड कांग्रेस को रसातल में ले जाने को आमादा हरीश रावत

दिव्य हिमगिरि

हिमालयी राज्यों की पहली साप्ताहिक पत्रिका

नज़र सब पर

15th ANNIVERSARY

वर्ष 15 | अंक 46 | मूल्य 05 रुपये | 05-11 अप्रैल, 2026

सदन में अपने ही सांसद के बोलने पर असहज हुई आप

जब किसी परिवार की खुशियां वापिस आती है तो बहुत खुशी होती हैः डॉ. दिव्या

लंबा इंतजार खत्म, 14 अप्रैल से दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे शुरू

दिव्य हिमगिरि

05-11 अप्रैल, 2026

संपादक
डॉ. कुँवर राज अस्थाना

वरिष्ठ संवाददाता
शंभूनाथ गौतम

संवाददाता
पूनम आर्या

विज्ञापन
सुनील सेमवाल

ग्राफिक डिजायनर
देव भट्ट

संवाददाता
हरिद्वार: डॉ. रजनीश गौतम
पौडी: रत्नमणि भट्ट
कोटद्वार: के.पी. बौंठियाल
रूद्रपुर: हेमचन्द्र बुडलाकोटी
चमोली: मुकेश रावत
रुड़की: श्रीगोपाल नारसन
नैनीताल: शीतल तिवारी
अल्मोड़ा: संजय कुमार अग्रवाल (एड.)
विकासनगर: अजय शर्मा
प्रसार: रमेश सिंह रावत

संपादकीय कार्यालय : 6, म्युनिसिपल रोड, बाला हिसार स्कूल के सामने, डालनवाला देहरादून (उत्तराखंड)
मोबाइल : +91 8433456398, 9410353164
Email: divyahimgiriddn@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक कुँवर बहादुर अस्थाना द्वारा सरस्वती प्रेस, 2, ग्रीन पार्क, निरंजनपुर, देहरादून से मुद्रित तथा 39/7 ई, ई. सी. रोड, (निकट मार्शल स्कूल सीनियर विंग) देहरादून-248001 उत्तराखण्ड से प्रकाशित।
संपादक: कुँवर बहादुर अस्थाना*
*(पीआरबी एक्ट के तहत प्रकाशित सामग्री के लिए उत्तरदायी)

टोल की मार

देशभर में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर पहले ही तोड़ रखी है। खाद्य पदार्थों से लेकर ईंधन और दैनिक उपयोग की वस्तुओं तक, हर क्षेत्र में कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे समय में यात्रा करना भी अब लोगों के लिए महंगा होता जा रहा है। वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और घरेलू नीतिगत निर्णयों के कारण पहले से ही आर्थिक दबाव झेल रहे नागरिकों पर अब टोल दरों में बढ़ोतरी एक नई चिंता के रूप में सामने आई है। हाल ही में हरियाणा के राजमार्गों पर टोल दरों में वृद्धि की घोषणा ने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा एकल और दोहरी यात्रा पर पांच रुपए से लेकर पैंतीस रुपए तक की बढ़ोतरी का निर्णय आम जनता के लिए असुविधाजनक साबित हो सकता है। गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेस-वे स्थित बजघेड़ा टोल प्लाजा पर एकल यात्रा के लिए 225 रुपए का शुल्क वसूलना न केवल निजी वाहन चालकों के लिए भारी है, बल्कि यह संकेत देता है कि यात्रा अब एक महंगी आवश्यकता बनती जा रही है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि टोल दरों में वृद्धि उस समय की जा रही है, जब अधिकांश राजमार्गों पर बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। यात्रियों को साफ-सुथरे शौचालय, पेयजल, विश्राम स्थल जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलतीं। कई स्थानों पर सड़कों की हालत खराब है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। रात के समय पर्याप्त रोशनी न होने के कारण हादसों की आशंका और भी बढ़ जाती है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब सुविधाएं अधूरी हैं, तो शुल्क में वृद्धि किस आधार पर की जा रही है? इसके अतिरिक्त, टोल प्लाजाओं पर लंबी कतारें भी एक बड़ी समस्या बनी हुई हैं। हालांकि फास्टैग और ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था लागू होने से कुछ हद तक सुधार की उम्मीद है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी कई जगहों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। इससे न केवल यात्रियों का समय बर्बाद होता है, बल्कि ईंधन की खपत भी बढ़ती है, जो अंततः महंगाई को और बढ़ावा देती है। टोल दरों में वृद्धि का प्रभाव केवल निजी वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहता। वाणिज्यिक वाहनों पर बढ़े हुए शुल्क का सीधा असर वस्तुओं की कीमतों पर पड़ता है, जिससे आम आदमी को अप्रत्यक्ष रूप से अधिक खर्च करना पड़ता है। इस प्रकार, टोल वृद्धि एक श्रृंखलाबद्ध प्रभाव उत्पन्न करती है, जिसका भार अंततः आम जनता को ही उठाना पड़ता है। सरकार और संबंधित प्राधिकरणों को यह समझना होगा कि विकास केवल राजस्व बढ़ाने से नहीं, बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने से होता है। यदि टोल दरों में वृद्धि अपरिहार्य है, तो इसके साथ ही राजमार्गों की गुणवत्ता, सुरक्षा और सुविधाओं में भी समान रूप से सुधार होना चाहिए। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित किए बिना केवल शुल्क बढ़ाना जनता के साथ अन्याय के समान है। अंततः यह कहना गलत नहीं होगा कि वर्तमान परिस्थितियों में टोल दरों में बढ़ोतरी आम लोगों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डाल रही है। जरूरत इस बात की है कि सरकार संतुलित और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाए, ताकि विकास और जनहित के बीच सामंजस्य बना रहे। तभी सच्चे अर्थों में "सुगम और सुरक्षित यात्रा" का सपना साकार हो सकेगा।

डॉ. कुँवर राज अस्थाना

लंबा इंतजार खत्म, 14 अप्रैल से दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे शुरू

शंभू नाथ गौतम
वरिष्ठ पत्रकार

लंबे समय से प्रतीक्षित दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे आखिरकार 14 अप्रैल से आम जनता के लिए खुलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके उद्घाटन करेंगे, जबकि 19 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा से पहले इस हाईस्पीड कॉरिडोर की शुरुआत को उत्तराखंड के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है। एक्सप्रेस-वे के चालू होने से दिल्ली से देहरादून की दूरी घटकर करीब 213 किलोमीटर रह जाएगी और सफर सिर्फ ढाई घंटे में पूरा हो सकेगा, जो अभी 5-6 घंटे का है। अक्षरधाम से बागपत तक का 18 किलोमीटर हिस्सा पहले ही खोला जा चुका है, जबकि पूरा मार्ग अब एक साथ चालू होगा। राजाजी नेशनल पार्क के इको-सेंसिटिव जोन में 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडोर और डाट काली मंदिर के पास 340 मीटर सुरंग भी बनाई गई है। चारधाम यात्रा, पर्यटन और कनेक्टिविटी को रफ्तार देने वाली इस परियोजना को धामी सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है।

देवभूमि उत्तराखंड के लिए लंबे समय से जिस परियोजना का इंतजार किया जा रहा था, वह अब हकीकत बनने जा रही है। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे 14 अप्रैल को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बहुप्रतीक्षित एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करेंगे। चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने से ठीक पहले इस हाईस्पीड कॉरिडोर की शुरुआत को उत्तराखंड के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है। इससे न केवल दिल्ली और देहरादून के बीच दूरी घटेगी, बल्कि पर्यटन, व्यापार और तीर्थयात्रा को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन से पहले एक्सप्रेस-वे का वीडियो साझा करते हुए तैयारियों की जानकारी दी थी। लंबे समय से देवभूमि में इस परियोजना को लेकर उत्सुकता बनी हुई थी। राज्य सरकार इसे कनेक्टिविटी सुधारने की दिशा में बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रही है। खासतौर पर चारधाम यात्रा से पहले इसके शुरू होने से यात्रियों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। एक्सप्रेस-वे शुरू होने के बाद दिल्ली से देहरादून का सफर बेहद आसान हो जाएगा। नई सड़क के जरिए दूरी घटकर लगभग 213 किलोमीटर रह जाएगी और यात्रा समय करीब ढाई घंटे में सिमट जाएगा। अभी दिल्ली से देहरादून पहुंचने में सामान्य तौर पर 5 से 6 घंटे का समय लगता है, जो ट्रैफिक के कारण कई बार और बढ़ जाता है। ऐसे में यह एक्सप्रेस-वे उत्तराखंड के लिए लाइफलाइन साबित हो सकता है। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे का कुछ हिस्सा पहले ही आम जनता के लिए खोला जा चुका है। अक्षरधाम से बागपत तक का लगभग 18 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच पहले ही चालू कर दिया गया था। इस हिस्से के खुलने के बाद यात्रियों को आंशिक राहत मिली थी, लेकिन अब पूरे एक्सप्रेस-वे के खुलने के साथ हाईस्पीड कनेक्टिविटी पूरी तरह से स्थापित हो जाएगी। सड़क परिवहन और

चारधाम यात्रा से पहले हाईस्पीड कनेक्टिविटी की सौगात

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे के शुरू होने के साथ ही उत्तराखंड की कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 14 अप्रैल को उद्घाटन के बाद यह एक्सप्रेस-वे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। चारधाम यात्रा से पहले इसके शुरू होने को रणनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं। इस एक्सप्रेस-वे के शुरू होने से दिल्ली से देहरादून का सफर ढाई घंटे में पूरा हो सकेगा। अभी तक यह यात्रा 5 से 6 घंटे में पूरी होती है। कई बार जाम और ट्रैफिक दबाव के कारण यात्रियों को और अधिक समय लग जाता है। नई हाईस्पीड सड़क इस समस्या का समाधान करने में मदद करेगी। यह एक्सप्रेस-वे आधुनिक इंजीनियरिंग का उदाहरण भी है। राजाजी नेशनल पार्क से गुजरने वाले हिस्से में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है। यह एशिया का सबसे लंबा 12 किलोमीटर का एलिवेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडोर बताया जा रहा है। इसके अलावा 340 मीटर लंबी सुरंग भी बनाई गई है। डाट काली मंदिर के पास बनी यह सुरंग विशेष रूप से वन्यजीवों को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। इसके अलावा गणेशपुर-देहरादून सेक्शन में कई एनिमल पैसेज बनाए गए हैं। इससे जानवर सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सकेंगे और दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी। एक्सप्रेस-वे का कुछ हिस्सा पहले ही खोला जा चुका है। अक्षरधाम से बागपत तक 18 किलोमीटर का स्ट्रेच पहले से चालू है। इस हिस्से के खुलने के बाद यात्रियों को आंशिक राहत मिली थी। अब पूरे एक्सप्रेस-वे के शुरू होने से दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा पूरी तरह से हाईस्पीड हो जाएगी। राज्य सरकार इस परियोजना को बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रही है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और चारधाम यात्रा के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। साथ ही उत्तराखंड में निवेश और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है।

राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, इस एक्सप्रेस-वे का अंतिम लगभग 20 किलोमीटर हिस्सा राजाजी नेशनल पार्क के इको-सेंसिटिव जोन से होकर गुजरता है। वन्यजीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहां एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडोर तैयार किया गया है, जिसकी लंबाई करीब 12 किलोमीटर है। इसके साथ ही 340 मीटर लंबी सुरंग भी बनाई गई है, जिससे जानवरों के प्राकृतिक आवागमन पर असर कम से कम पड़े। देहरादून में डाट काली मंदिर के पास बनाई गई यह सुरंग परियोजना का अहम हिस्सा मानी जा रही है। इसके अलावा गणेशपुर-देहरादून सेक्शन में कई एनिमल पैसेज बनाए गए हैं, ताकि वन्यजीव सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सकें और वाहनों से टक्कर की घटनाओं को रोका जा सके। यह एक्सप्रेस-वे पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का संतुलित उदाहरण माना जा रहा है।चारधाम यात्रा से पहले इस एक्सप्रेस-वे का शुरू होना तीर्थयात्रियों के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है। हर साल यात्रा के दौरान दिल्ली-देहरादून और हरिद्वार मार्ग पर भारी दबाव रहता है। नए एक्सप्रेस-वे के खुलने से यातायात का दबाव कम होगा और यात्रा अधिक सुगम होगी। साथ ही राज्य में पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार के लिए भी यह परियोजना अहम उपलब्धि के तौर पर देखी जा रही है। बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से निवेश, उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। दिल्ली-एनसीआर से उत्तराखंड पहुंचना आसान होने से वीकेंड पर्यटन को भी नई गति मिल सकती है। लंबे समय से प्रतीक्षित यह एक्सप्रेस-वे अब उत्तराखंड की विकास यात्रा में नई रफ्तार जोड़ने जा रहा है।

धामी सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन उत्तराखंड के विकास के लिहाज से अहम माना जा रहा है। 14 अप्रैल को इसके शुरू होने के साथ ही राज्य को नई हाईस्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी। चारधाम यात्रा से पहले इसका चालू होना राज्य सरकार के लिए भी बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पर्यटक और तीर्थयात्री दोनों को बड़ी राहत मिलेगी। खासतौर पर वीकेंड पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। राजाजी नेशनल पार्क से गुजरने वाले हिस्से को पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया है। यहां 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडोर बनाया गया है। इसके साथ ही 340 मीटर लंबी सुरंग भी तैयार की गई है। यह सुरंग डाट काली मंदिर के पास बनाई गई है। गणेशपुर-देहरादून सेक्शन में एनिमल पैसेज भी बनाए गए हैं। इससे वन्यजीवों और वाहनों की टक्कर की घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी। यह परियोजना विकास और पर्यावरण संरक्षण का संतुलन भी दिखाती है। अब पूरे एक्सप्रेस-वे के चालू होने से दिल्ली-एनसीआर से उत्तराखंड पहुंचना आसान हो जाएगा। इससे होटल, ट्रैवल और स्थानीय कारोबार को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। चारधाम यात्रा से पहले इस एक्सप्रेस-वे का शुरू होना श्रद्धालुओं के लिए राहत लेकर आएगा। हर साल यात्रा के दौरान भारी ट्रैफिक रहता है। नए एक्सप्रेस-वे से दबाव कम होगा और यात्रा सुगम बनेगी। राज्य सरकार इसे विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रही है।

सोशल मीडिया पर आजकल हरीश रावत बहुत सुर्खियां बटोर रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि वह 15 दिनों के अर्जित अवकाश पर जा रहे हैं। उनके इस बयान से राजनैतिक सरगर्मियां बढ़ गई। उनका अर्जित अवकाश कांग्रेस हाईकमान के प्रति नाराजगी मानी जा रही है। सोशल मीडिया पर उनके समर्थकों ने कांग्रेस छोड़ने की धमकी भरे बयान देने शुरू कर दिए। ऐसा क्या हुआ कि हरीश रावत राजनैतिक अवकाश पर जाने की बात करने लगे। बता रहें है वरिष्ठ पत्रकार लेखक डॉ. कुँवर राज अस्थाना।

उत्तराखंड कांग्रेस को रसातल में ले जाने को आमादा हरीश रावत

अभी कुछ दिनों पूर्व नई दिल्ली में भाजपा के कुछ कद्दावर नेताओं को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराने को लेकर एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में भाजपा के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, भीमलाल आर्या, और नारायण पाल सहित तीन अन्य गौरव गोयल, अनुज गुप्ता तथा लाखन सिंह को पार्टी में शामिल किए जाने पर एकराय बनी। इसी मीटिंग में हरीश रावत ने रामनगर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले संजय नेगी को भी ज्वाइन कराने का सुझाव दिया। जिसे मीटिंग में शामिल अन्य सभी नेताओं ने एकमत से खारिज कर दिया। हरीश रावत इसी बात से नाराज बताए जा रहे हैं। नाराज हरीश रावत 15 दिनों के अर्जित अवकाश पर चले गए। उनके खास समर्थक कहे जाने वाले धारचूला के विधायक हरीश धामी एक वीडियो में कहते नजर आए कि वह 2027 का चुनाव नहीं लडेंगे। इसे कांग्रेस हाईकमान पर प्रेशर टैक्टिस के रूप में देखा जा रहा है। कभी उनके खास रहे अब भाजपा का दामन थाम चुके पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल कहते हैं कि 'कांग्रेस में कौन हेडमास्टर है जो अर्जित अवकाश स्वीकृत करता है।' चकराता से विधायक एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह कहते हैं कि 'जिस व्यक्ति का 60 वर्ष का राजनैतिक जीवन हो, क्या उसे 15 दिन का अवकाश लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए!' पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि 'हरीश रावत बडे नेता हैं, जरूरी नहीं है कि उनका उपयोग हर छोटी जगह हो' । कांग्रेस में मचे इस घमासान के बीच प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का एक गाना बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वह हारमोनियम के साथ ताल मिला कर गा रहे है 'तेरी अदाओं पर मर-मर गये हम' मानों कि उनके लिए हरीश रावत की नाराजगी की प्रासंगिकता ही नहीं है।

इसी बीच एक फोटो जिसमें भाजपा सरकार में शामिल हुए एक नये मंत्री खजान दास फूलों के गुलदस्ते के साथ हरीश रावत के घर पर नजर आ रहे हैं, खूब वायरल हो रहा है। राजनैतिक प्रेक्षकों का मानना है कि कांग्रेस हाईकमान पर दबाव बनाने के लिए हरीश रावत भाजपा नेताओं का सहारा ले रहे हैं। राजनैतिक प्रेक्षकों की माने तो आज कांग्रेस में तीन बडे चेहरे हैं: हरीश रावत, प्रीतम सिंह और यशपाल आर्या। प्रीतम सिंह और यशपाल आर्या आजतक कोई विधानसभा चुनाव नहीं हारे जबकि हरीश रावत केवल एक ही विधानसभा चुनाव जीत पाए जो उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में उपचुनाव लड़ा था। हरीश रावत अपने 60 वर्षों के संसदीय जीवन में कुल जमा 3 चुनाव ही जीत पाए। लेकिन इसके बावजूद वह कांग्रेस के क्षत्रप बने रहने में कामयाब रहे क्योंकि वह हमेशा नकारात्मक राजनीति करते रहे। 2002 में हुए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया। उस समय हरीश रावत प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपना दावा प्रस्तुत किया लेकिन हाईकमान ने नारायणदत्त तिवारी को मुख्यमंत्री बनाना बेहतर समझा। हरीश रावत ने 5 वर्षों तक यह माहौल बनाकर राज्य सरकार के सामने कांटे बिछाए कि कांग्रेस में विभाजन हो सकता है। कांग्रेस के राज्य प्रभारी मोतीलाल वोरा के देहरादून दौरे के दौरान हरीश रावत समर्थकों ने कांग्रेस के कार्यालय में मोतीलाल वोरा के सामन गमले तक तोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। हरीश रावत मुख्यमंत्री न बन सके

लेकिन उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों को मंत्री बनावाया और राज्यमंत्री दर्जाप्राप्त दायित्वध ाारी बनवाया। 2007 के विधानसभा चुनाव के बाद हरीश रावत यूकेडी, बसपा और निर्दलियों के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए उतावले थे। लेकिन एक नाटकीय घटनाक्रम में कांग्रेस हाईकमान के आदेश पर पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने नई दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस करके सरकार बनाने का दावा करने से मना कर दिया। 2012 में भी कांग्रेस ने हरीश रावत की बजाए विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाया। यानि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद के लिए हरीश रावत कांग्रेस हाईकमान की पसंद न 2002 में थे, न 2007 में और न ही 2012 में थे।

हरीश रावत ने कांग्रेस की प्रचंड लहर में अपना पहला चुनाव 1980 में अल्मोड़ा संसदीय सीट से जीता था, उन्होंने मुरली मनोहर जोशी जैसे भाजपा के कद्दावर नेता को चुनाव हराया था। यहीं से कांग्रेस में उनका कद क्षत्रप वाला बना। लेकिन उसके बाद हरीश रावत को अल्मोड़ा में लगातार हार का सामना करना पड़ा। लगातार हार का सामना करने के बाद 2009 में हरीश रावत ने अल्मोड़ा से पलायन करके हरिद्व ार से टिकट मांगा। पौड़ी संसदीय सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सतपाल महाराज और टिहरी संसदीय सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विजय बहुगुणा ने युति बनाकर हरीश रावत की दावेदारी का यह कहकर समर्थन किया कि हरीश रावत के लिए यह नया संसदीय क्षेत्र है, यहां चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे तो दूसरों के लिए मुसीबतें खड़ा करने का उनको समय नहीं मिलेगा। वास्तव में सतपाल महाराज और विजय बहुगुणा की यह युति काम आई और कांग्रेस उत्तराखंड की पांचों सीट जीत गई। जब 2014 में जब कांग्रेस हाईकमान ने आपदा में सही तरह से काम न कर पाने के आरोप में विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री पद से हटाया तब हरीश रावत केंद्र में जल संसाधन मंत्री थे। उन्होंने 2014 में अपनी हरिद्वार संसदीय सीट से अपनी पत्नी रेणुका रावत को चुनाव लड़वाया। हरीश रावत 2009 में हरिद्वार से 1,27,000 वोट के अंतर से जीते थे लेकिन उनकी पत्नी 2014 में 1,70,000 वोट के अंतर से चुनाव हारी। हरिद्वार सीट से 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी अंबरीश कुमार तो 2024 में हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत चुनाव हारे। अलबत्ता हरीश रावत मुख्यमंत्री बनने के बाद जुलाई 2014 में धारचूला विधानसभा उपचुनाव में 20,000 वोट के अंतर से जीतकर पहली बार विधायक बने, यह सीट हरीश धामी ने उनके लिए छोड़ी थी।

मुख्यमंत्री के रूप में हरीश रावत पर भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे। नेतृत्व के मामले में तो वह लगभग फेलियर नजर आए। उनके खासमखास टिहरी के तत्कालीन विधायक और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष किशोर उपाध्याय उनके खिलाफ मुखर नजर आए। पार्टी में उनके कामकाज को लेकर लगातार अंतरविरोध बढ़ता ही जा रहा था। अंतत: इसकी परिणिति यह हुई कि उत्तराखंड कांग्रेस में विभाजन हो गया। 9 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। 21 अप्रैल, 2016 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। लेकिन हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 11 मई, 2016 को हरीश रावत पुन: मुख्यमंत्री बने। लेकिन कांग्रेस में बगावत का सिलसिला चलता रहा। 02 विधायकों ने और इस्तीफा दे दिया। यानि मुख्यमंत्री के रूप में हरीश रावत कांग्रेस के कुनबे को एकजुट रखने में नाकामयाब रहे। 2017 में राज्य में विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस में हुए विभाजन से भी हरीश रावत ने कोई सबक नहीं लिया। कांग्रेस को एकजुट करके चुनाव लड़ने की बजाय हरीश ने सहसपुर से कांग्रेस के जिताऊ प्रत्याशी का टिकट कटवा दिया और टिहरी से प्रदेशाध्यक्ष किशोर उपाध्याय का भी टिकट कटवा दिया। अपने आप हरीश रावत ने हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। लेकिन दोनों ही सीटों से हरीश रावत चुनाव हार गए। इस चुनाव में कांग्रेस 11 सीटों पर सिमट कर रह गई। 2022 में पुन: चुनाव की कमान हरीश रावत के हाथों में थी। इस बार पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर थी। इस लहर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खटीमा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे भाजपा के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं चुनाव हार गए थे। हरीश रावत इस चुनाव में रामनगर से चुनाव लड़ना चाहते थे क्योंकि यहां से उनके पूर्व राजनैतिक सलाहकार रणजीत सिंह रावत चुनाव की तैयारियां कर रहे थे। हरीश रावत उनको किसी भी कीमत पर विधायक नहीं देखना चाहते थे। रामनगर सीट पर इस कदर हंगामा बरपा कि हाईकमान ने अंतिम क्षण में हरीश रावत को लालकुआं, रणजीत रावत को सल्ट और रामनगर से पूर्व सांसद महेंद्र पाल को टिकट दे दिया। रामनगर में हरीश रावत के खास सिपाहसलार पूर्व ब्लाक प्रमुख संजय नेगी ने निर्दलीय ताल ठोंक दी। लालकुंआ में हरीश दुर्गापाल नाराज हो गए। सल्ट में भी हरीश रावत के समर्थक रणजीत रावत के खिलाफ हो गए। ऐसा ही कुछ सहसपुर सीट पर हुआ। सहसपुर हॉट सीट थी, वहां कांग्रेस की बनी लहर देहरादून की आधा दर्जन सीटों को प्रभावित कर रही थी। वहां हरीश रावत समर्थक एवं कांग्रेस नेता अकील अहमद ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय नामांकन कर दिया। जब अकील पर नामांकन वापिस लेने का दबाव पड़ा तो उसने एक प्रेस कांफ्रेंस करके एक मांग पत्र पढ़कर अपना नामांकन वापिस लेने की घोषणा कर दी। उसने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि मैंने अपनी अन्य मांगों में एक मांग यह की है कि सहसपुर में एक मुस्लिम युनिवर्सिटी बनाई जाएं, मैंने अपनी इस मांग से हरीश रावतजी को भी अवगत करा दिया है। अकील अहमद के इस बयान को भाजपा ने रातो रात मुद्दा बनाकर ध्रुवीकरण कर दिया। लेकिन अकील अहमद के इस बयान पर हरीश रावत ने मौन साध लिया। नतीजतन कांग्रेस सहसपुर, विकासनगर, देहरादून कैंट, राजपुर, धर्मपुर और मसूरी जैसी जिताऊ सीटें हार गई। ऐसे ही कांग्रेस रामनगर, और सल्ट भी हार गई। दूसरों के लिए गुणा भाग करते हुए हरीश रावत भी लालकुंआ से चुनाव हार गए।

इस प्रकार हरीश रावत 1980 से लेकर 2024 तक 54 वर्षों के संसदीय जीवन में केवल तीन चुनाव ही जीत पाए। हालांकि उनपर आरोप है कि उनको सीटे हरवाने का बहुत अनुभव है। नाम न छापन की शर्त पर कांग्रेस के शीर्ष नेता का कहना है कि ''चूंकि हरीश रावत पर मुख्यमंत्री के रूप में कई संगीन भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उनको सीबीआई और एसआईटी ने भी अपने जांच के चंगुल में फंसाया हुआ है, अत: वह भाजपा के सामने कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने के लिए संसाधन ही उपलब्ध नहीं कराए, जो प्रत्याशी अपने दमपर चुनाव लड़ रहे थे, उनकी राह में कांटे बिछाए और कुछ जिताऊ प्रत्याशियों के टिकट कटवाकर कांगेस को 11 के आंकड़े तक सिमटा दिया। 2022 में भी कुछ ऐसा ही खेल रचा कि कांग्रेस सत्ता में न आ सके। और वही खेल 2027 में भी रचने के लिए उन्होंने बिसात बिछा दी हैं। इस बार भी केंद्र 'रामनगर' है। हरीश रावत अपने बेटे को धर्मपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। यदि उनके बेटे को इस चुनाव में टिकट मिलता है तो वह पुन: चुनाव सक्रिय होकर 2022 वाला गेम खेलेंगे। हरीश रावत जबतक सक्रिय राजनीति में रहेंगे वह किसी अन्य के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने देंगे।''

क्या उत्तराखंड कांग्रेस में 'शक्ति' संतुलन बिगड़ेगा

उत्तराखंड कांग्रेस में शक्ति संतुलन बिगड़ता नजर आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 'हरदा' के अर्जित अवकाश को लेकर शुरू हुई चर्चा ने संगठन के भीतर शक्ति संतुलन पर नई बहस छेड़ दी है। हरदा के कुछ समय के लिए सक्रिय राजनीति से दूरी की अटकलों के बीच प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष प्रीतम सिंह और चुनाव प्रबंधन समिति अध्यक्ष डॉ. हरक सिंह रावत की 'त्रिमूर्ति' के सक्रिय होने से सियासी समीकरण बदलते दिख रहे हैं। हालांकि हरदा अपनी राजनीतिक पकड़ कमजोर पड़ने देने के मूड में नहीं हैं, जिससे नेतृत्व को लेकर अंदरखाने शक्ति परीक्षण की स्थिति बन गई है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी प्रांतीय कार्यकारिणी का गठन लंबित रहने से असमंजस बना हुआ है। हाल में कुछ नेताओं को पार्टी में शामिल किए जाने और कुछ को नजरअंदाज किए जाने को लेकर भी नाराजगी की चर्चा है। पार्टी इसे आंतरिक लोकतंत्र बता रही है, लेकिन लगातार बढ़ती बयानबाजी ने चुनाव से पहले एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में एकजुट होकर मैदान में उतरने का दावा कर रही भाजपा के मुकाबले कांग्रेस की रणनीति को लेकर भी नए सवाल उठने लगे हैं। दिव्य हिमगिरि रिपोर्ट।

उत्तराखंड कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 'हरदा' के अर्जित अवकाश को लेकर शुरू हुई चर्चा ने संगठन के भीतर सियासी हलचल तेज कर दी है। पार्टी के भीतर इसे नेतृत्व की नई पंक्ति के उभरने और पुराने नेतृत्व के प्रभाव के बीच शक्ति परीक्षण के रूप में देखा जा रहा है। हरदा के कुछ समय के लिए सक्रिय राजनीति से दूरी बनाने की बात सामने आने के बाद प्रदेश संगठन में नए समीकरण बनने लगे हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉ. हरक सिंह रावत की 'त्रिमूर्ति' को लेकर चर्चाएं तेज हैं, जबकि हरदा अपने प्रभाव को बनाए रखने की कोशिश में सक्रिय माने जा रहे हैं। पार्टी के भीतर यह भी कहा जा रहा है कि हरदा का अर्जित अवकाश केवल व्यक्तिगत निर्णय भर नहीं है, बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। लंबे समय से उत्तराखंड कांग्रेस की राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभाते रहे हरदा की सक्रियता कम होने की संभावना ने दूसरे नेताओं को अधिक सक्रिय होने का मौका दिया है। संगठनात्मक बैठकों से लेकर राजनीतिक संदेशों तक में नई लाइन उभरती दिखाई दे रही है। हालांकि हरदा के समर्थक मानते हैं कि उन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा और उनकी पकड़ अब भी जमीनी स्तर पर मजबूत है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद गणेश गोदियाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रांतीय कार्यकारिणी का गठन माना जा रहा है। कार्यकारिणी गठन में हो रही देरी ने भी अंदरूनी असमंजस को बढ़ाया है। कई नेता अपने-अपने समर्थकों को जगह दिलाने की कोशिश में लगे हैं, जिससे संतुलन साधना मुश्किल हो रहा है। सूत्रों के अनुसार, विभिन्न धड़ों के बीच सहमति न बन पाने के कारण सूची बार-बार टल रही है। इससे यह संदेश भी जा रहा है कि संगठन के भीतर एक राय बनाना आसान नहीं रह गया है। हाल ही में कुछ पूर्व विधायकों और नेताओं को कांग्रेस में शामिल किए जाने के दौरान भी असंतोष की खबरें सामने आईं। रामनगर क्षेत्र से जुड़े एक नेता को शामिल नहीं किए जाने को लेकर हरदा की नाराजगी की चर्चा रही। हालांकि पार्टी स्तर पर इसे सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया बताया गया, लेकिन अंदरखाने इसे गुटबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस घटनाक्रम ने यह संकेत दिया कि टिकट वितरण और संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर खींचतान अभी और बढ़ सकती है। हरदा के अर्जित अवकाश पर पार्टी के कुछ नेताओं की बयानबाजी ने भी विवाद को हवा दी है। किसी ने इसे पीढ़ी परिवर्तन का संकेत बताया तो किसी ने इसे संगठन में नए नेतृत्व के उभरने का मौका कहा। दिलचस्प यह है कि इन बयानों पर पार्टी नेतृत्व की ओर से अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई। आधिकारिक तौर पर यही कहा गया कि कांग्रेस में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और नेताओं को अपनी बात रखने की आजादी है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि लगातार सार्वजनिक बयान संगठन की एकजुटता को प्रभावित कर सकते हैं।

प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के प्रस्तावित दौरे से पहले यह हलचल और बढ़ गई है। माना जा रहा है कि अलग-अलग धड़े अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में जुटे हैं, ताकि केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी स्थिति मजबूत की जा सके। बैठक से पहले बयानबाजी और सक्रियता को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पार्टी के भीतर यह भी चर्चा

है कि संगठनात्मक ढांचे को जल्द अंतिम रूप दिया जाए, ताकि चुनावी तैयारी को गति मिल सके। इस बीच भाजपा के एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने के दावे ने कांग्रेस के भीतर चिंता भी बढ़ाई है। भाजपा लगातार संगठनात्मक विस्तार और बूथ स्तर की मजबूती पर काम कर रही है, जबकि कांग्रेस अभी भी आंतरिक संतुलन साधने में लगी दिखाई दे रही है। ऐसे में नेतृत्व को लेकर जारी खींचतान का असर पार्टी की रणनीति पर पड़ सकता है।

फरवरी 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस में बढ़ती चुनौती

फरवरी 2027 में प्रस्तावित उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन को एकजुट करना है। पार्टी ने सत्ता में वापसी का लक्ष्य तय किया है, लेकिन इसके लिए मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट रणनीति जरूरी मानी जा रही है। हरदा के अनुभव और जनाधार को नजरअंदाज करना पार्टी के लिए आसान नहीं है, वहीं नए नेतृत्व की सक्रियता को भी संतुलित करना जरूरी है। यही कारण है कि नेतृत्व के बीच तालमेल का मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि कांग्रेस समय रहते आंतरिक मतभेदों को सुलझा लेती है, तो वह चुनावी मुकाबले में मजबूती से उतर सकती है। लेकिन यदि गुटबाजी बढ़ती है, तो इसका सीधा फायदा प्रतिद्वंद्वी दलों को मिल सकता है। टिकट वितरण, संगठनात्मक नियुक्तियों और चुनावी रणनीति जैसे मुद्दे आने वाले समय में इस खींचतान को और तेज कर सकते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि कांग्रेस का इतिहास सामूहिक नेतृत्व का रहा है और सभी नेताओं को साथ लेकर चलना ही समाधान है। केंद्रीय नेतृत्व भी संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों को तेज करने पर जोर दे रहा है। ऐसे में आने वाले महीनों में यह देखना अहम होगा कि हरदा और त्रिमूर्ति के बीच तालमेल बनता है या सियासी खींचतान और गहराती है। उत्तराखंड कांग्रेस इस समय संक्रमण के दौर से गुजर रही है। एक ओर अनुभवी नेतृत्व का प्रभाव है, तो दूसरी ओर नई टीम अपनी भूमिका मजबूत करने में जुटी है। फरवरी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए सबसे अहम चुनौती यही है कि वह इस शक्ति संतुलन को साधते हुए एकजुट होकर मैदान में उतरे। तभी वह मजबूत मुकाबले की स्थिति बना सकेगी।

क्षेत्र का लगातार विकास कराना ही सर्वोच्च प्राथमिकता है: भूपेंद्र कठैत

अपनी पारिवारिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं।

मेरा जन्म उत्तराखंड के चमोली जनपद के एक उच्च शिक्षित परिवार में हुआ है। हमारे परिवार की बैकग्राउंड खेती, पुलिस तथा आर्मी की रही है। मेरे दादा फौज से रिटायर्ड थे और कालागढ़ में हमारी खेती-बाडी थी इसिलिए मेरा बचपन वहीं पर बीता। मेरे पिता पुलिस में डीएसपी के पद पर कार्यरत थे तथा उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में उन्होंने अपनी सेवाएं दी और 3 बार राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित हुए। मेरी एक बहन स्पोर्टस में उत्तराखंड की पहली नेट क्वालीफाई लड़की है और जनपद मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) में में हैड ऑफ डिपार्टमेंट स्पोर्टस के पद पर कार्यरत है। शिक्षा के प्रति मेरा शुरू से ही झुकाव रहा है तथा मैने बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, मार्केट मैनेजमेंट और कम्प्यूटर कोर्स इत्यादि किए है।

राजनीति के क्षेत्र में आने के प्रेरण ाास्रोत्र कौन रहे है?

मैं एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था और बीच-बीच में लोगों के रोजमर्रा के कार्यों में उनकी मदद भी करता रहता था। कॉलोनी की सोसायटियों के बड़े बुजुर्गो ने ही मुझे राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया और युवाओं के जोश और बडों के आर्शीवाद ने मुझे पहली बार देहरादून नगर निगम के पार्शद के रूप में चुनाव जितवाया। तब से अब तक नगर निगम पार्शद के रूप में यह मेरा चौथा कार्यकाल है। मुझे जनता का इतना प्यार और आर्शीवाद मिल रहा है कि पार्शद के रूप में हर बार मेरी जीत का मार्जन बढ़ता जा रहा है।

आपकी उपलब्धियों के बारे में बताइये।

मेरा वार्ड 8 सालावाला हाथीबड़कला एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें दिलाराम चौक, हाथीबडकला, सालावाला, न्यू कैंट रोड, आरटीओ चंद्रलोक, ब्रजलोक, राजपुर रोड सहित सीएम हाउस तक का क्षेत्र आता है। मैने अपने क्षेत्र में अभी तक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, पम्पिंग स्टेशन तथा लगभग चार से पांच टयूबवैल लगवाएं है। इसके अलावा कालोनी के पार्कों का तथा मंदिरों का सौन्दर्यीकरण कराया गया है और अब मैं अपने क्षेत्र के बड़े-बुजुर्गो/बच्चों के घूमने, खेलने, योग इत्यादि करने के लिए 4 से 5 किमी0 के दायरे में एक बड़ा पार्क (लगभग 5 बीघा में) बनाने की दिशा में कार्य कर रहा हूॅ। यह पार्क मेरे क्षेत्र के सैन्टर प्वाइंट में होगा और आरटीओ से चंद्रलोक कॉलोनी, ब्रजलोक, सालावाला सहित कई जगहों को कवर करेगा। इसके अलावा सालावाला का पुराना पुल जो अंग्रेजों के समय का बना हुआ है और अब उसमें दरार भी आ चुकी है, को पुनर्निमाण कर चौड़ा करने का कार्य भी चल रहा है। इस पुल के लिए हमारे प्रदेष्ठा के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घोषणा भी कर चुके है और यह पुल पास होकर इसका टेंडर भी लग चुका है। जल्दी ही इस पुल के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मैं अपने क्षेत्र में एक और नई टयूबवैल लाने के लिए प्रयासरत हूॅ ताकि मेरे क्षेत्र की पानी की समस्या का स्थायी निदान हो जाए।

जब किसी परिवार की खुशियां वापिस आती है तो बहुत खुशी होती है: डॉ. दिव्या

माइंड हील क्लीनिक में आने वाले मनोरोगियों का ईलाज करके उन्हें मुख्यधारा में वापिस लाने का सफलतापूर्वक कार्य करने वाली डॉ. दिव्या घई से उनके प्रोफेशनल सफर के बारे में लोकेश राज अस्थाना से हुई बातचीत के अंश-

डॉ. दिव्या घई
MBBS, MD Psychiatry, Sleep & Perinatal Specialist
कंसल्टेंट मनोचिकित्सक
माइंड हील क्लीनिक, देहरादून

अपनी पारिवारिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं

मेरा जन्म हरियाणा के यमुनानगर जिले के सढौरा गांव के एक शिक्षित परिवार में हुआ है। मैने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई सढौरा में रहकर ही पूरी की। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए मैं चंढ़ीगढ आ गई और यही पर मैने अपनी मेडिकल की कोचिंग भी पूर्ण की। मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मुझे मेरी रैंक के अनुसार पटियाला में गर्वमेंट मेडिकल कॉलेज (GMC) में दाखिला मिला और मैने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पूर्ण की। एमडी साइकेट्रिक डीएमसी कॉलेज लुधियाना से पूर्ण की।

चिकित्सा क्षेत्र में आने के प्रेरणास्रोत कौन रहे है?

चिकित्सा के क्षेत्र में आने का तो मैने बचपन से ही तय कर लिया था क्योंकि मुझे बचपन से ही बहुत शौक था कि मुझे आगे चलकर डाक्टर बनना है और इसके जरिए लोगों की मदद भी करनी है। चिकित्सा की मेरी इस जर्नी की प्रेरणास्रोत मेरी माताजी रही है। उन्होंने मुझे पढ़ाई में बहुत प्रोत्साहित किया क्योंकि ज्यादातर परिवारों में लड़कियों में पढ़ाई के लिए ज्यादा मोटिवेट नहीं किया जाता है लेकिन मेरे मामले में ठीक इसके अलग था। मेरी माता इस बात पर बिल्कुल क्लियर थी कि मुझे पढ़ाई में बहुत आगे जाना है और चिकित्सा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना है।

अपने प्रोफेशनल सफर के बारे में बताए और आपकी अब तक की क्या-क्या उपलब्धियां रही है?

डीएमसी लुधियाना से एमडी करने के बाद सुभारती मेडिकल कॉलेज, देहरादून में सीनियर रेजीडेंट के रूप में 1.5 साल, गर्वमेंट मेडिकल इंस्टीटयूट (मानसिक चिकित्सालय, सेलाकुंई में 6 महीने, दून मेडिकल कॉलेज में लगभग 2 वर्ष कार्य किया। दून मेडिकल कॉलेज से रिजाइन करने के बाद मैने माइंड हील क्लीनिक के नाम से अपना प्राइवेट हास्पिटल शुरू किया और अब यही पर कंसल्टेंट मनोचिकित्सक के रूप में प्रैक्टिस कर रही हूँ।

चिकित्सा के क्षेत्र में आपका कोई यादगार अनुभव।

चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे अनुभव हुए है। नशा करने वाले लोगों की लाइफ को करीब से देखने का मौका मिला है। नशे के आदि रहने वाले लोग अपने साथ-साथ अपने परिवार की लाईफ को भी खराब कर देते है। यादगार अनुभव के तौर पर मैं कह सकती हूँ कि मुझे कई पेशेंट ऐसे भी मिले है जो किसी कारणवश नशे की गिरफ्त में तो आ गये लेकिन जब उनका ईलाज शुरू हुआ तो उन्होंने मेरी हर एडवाइज को अच्छे से फॉलो किया, रेगुलर ट्रीटमेंट तथा दवाईयों को भी समय से लिया। इससे न केवल उनका स्वास्थ्य अच्छा हुआ बल्कि वे मुख्यधारा में वापिस आए और उनके परिवार में खुशियां भी लौट कर आई। इससे अच्छा यादगार अनुभव मेरे लिए और क्या हो सकता है।

दिव्य हिमगिरी के पाठकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी?

पाठकों के लिए मेरा संदेश है कि वे अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि अगर मन ठीक होगा तभी शरीर भी ठीक रहेगा। अगर आपके मस्तिष्क में कोई प्राब्लम रहेगी तो उसका इफेक्ट आपके शरीर के साथ-साथ आपके परिवार की सुख शांति पर भी पडेगा। अगर किसी को मानसिक समस्या जैसे डिप्रेशन, एंजाईटी, नशे की लत, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, व्यवहार में अचानक बदलाव आदि कुछ लक्षण आते है तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए और तुरन्त मनोचिकित्सक से सम्पर्क करना चाहिए और समय पर ईलाज शुरू कराना चाहिए। ये कोई शर्म वाली बात नहीं है। जैसे और बीमारी होती है इसी तरह मानसिक समस्या भी एक बीमारी है और सबसे अच्छी बात है कि अब इसका ईलाज बहुत सेफ है और अच्छे से उपलब्ध भी है।

सदन में अपने ही सांसद के बोलने पर असहज हुई आप

आम आदमी पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को उच्च सदन में पार्टी के उपनेता पद से हटाकर बड़ा संगठनात्मक संदेश दिया है। पार्टी ने इस संबंध में राज्यसभा सचिवालय को आधिकारिक पत्र भेजते हुए अनुरोध किया है कि चड्ढा को तत्काल प्रभाव से उपनेता पद से मुक्त किया जाए और उन्हें पार्टी कोटे से सदन में बोलने का समय भी आवंटित न किया जाए। पार्टी ने उनकी जगह सांसद अशोक मित्तल को नया उपनेता बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस फैसले को संसदीय रणनीति में बदलाव के साथ-साथ पार्टी के भीतर नेतृत्व संतुलन के रूप में देखा जा रहा है। हाल के महीनों में राघव चड्ढा द्वारा संसद में लगातार जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए जाने और संगठनात्मक गतिविधियों से उनकी दूरी को भी इस निर्णय से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पार्टी ने औपचारिक रूप से कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन इस कदम ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। दिव्य हिमगिरि रिपोर्ट

आम आदमी पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को उच्च सदन में पार्टी के उपनेता पद से हटाकर बड़ा संगठनात्मक फैसला लिया है। पार्टी ने इस संबंध में राज्यसभा सचिवालय को आधिकारिक पत्र भेजते हुए अनुरोध किया है कि चड्ढा को तत्काल प्रभाव से उपनेता पद से मुक्त किया जाए और उन्हें पार्टी कोटे से सदन में बोलने का समय भी आवंटित न किया जाए। पार्टी ने उनकी जगह सांसद अशोक मित्तल को नया उपनेता बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस कदम को संसदीय रणनीति में बदलाव और नेतृत्व में फेरबदल के तौर पर देखा जा रहा है। अप्रैल 2022 से राज्यसभा सांसद रहे राघव चड्ढा सदन में मुखर आवाज के रूप में जाने जाते रहे हैं, लेकिन हाल के महीनों में उनकी संगठनात्मक सक्रियता कम दिखाई देने की चर्चा भी चल रही थी। पार्टी द्वारा भेजे गए पत्र में स्पष्ट संकेत दिया गया है कि संसदीय मंच पर पार्टी की लाइन तय करने और बोलने के अवसरों को लेकर नया ढांचा तैयार किया जा रहा है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 10 सदस्य हैं, जिनमें सात पंजाब और तीन दिल्ली से हैं। ऐसे में उपनेता पद का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि यही पद सदन में पार्टी के समन्वय और रणनीति तय करने में अहम भूमिका निभाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला पिछले कुछ समय से चल रहे आंतरिक मूल्यांकन और जिम्मेदारियों के पुनर्वितरण का हिस्सा हो सकता है।

राघव चड्ढा पिछले कुछ समय से पार्टी की प्रमुख राजनीतिक गतिविधियों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम नजर आ रहे थे। हाल ही में जारी स्टार प्रचारकों की सूची में भी उनका नाम शामिल नहीं किया गया था, जिसे नेतृत्व स्तर पर बदलाव के संकेत के तौर पर देखा गया। पार्टी की बैठकों और मीडिया ब्रीफिंग में उनकी अनुपस्थिति को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा रही। यहां तक कि दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को राहत मिलने के बाद भी उन्होंने सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे अटकलें और तेज हो गईं। हालांकि संसदीय मंच पर राघव चड्ढा पहले काफी सक्रिय रहे हैं। उन्होंने गिग वर्कर्स के सामाजिक सुरक्षा अधिकारों, पितृत्व अवकाश को कानूनी दर्जा देने, मिडिल क्लास पर टैक्स के बोझ और उपभोक्ता हितों से जुड़े कई मुद्दे उठाए थे। उनके इन बयानों को व्यापक समर्थन भी मिला था। इसके बावजूद पार्टी ने संसदीय नेतृत्व में बदलाव करते हुए उन्हें उपनेता पद से हटाने का निर्णय लिया है।

पद से हटने के बाद राघव चड्ढा ने कहा- 'खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं'

पद से हटाए जाने के बाद 3 अप्रैल को राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वे लगातार आम लोगों से जुड़े मुद्दे संसद में उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। उन्होंने मिडिल क्लास पर बढ़ते टैक्स, बैंक खातों में न्यूनतम बैलेंस पर जुर्माना, मोबाइल कंपनियों के 28 दिन वाले रिचार्ज, एयरपोर्ट पर महंगे खाने, हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी, प्रदूषण और पेपर लीक जैसे मुद्दों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन विषयों को उठाने के कारण उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। चड्ढा ने अपने संदेश में लिखा, "खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं।" साथ ही उन्होंने शायराना अंदाज में कहा, "मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है।" उनके इस बयान को पार्टी नेतृत्व पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है।

राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के प्रमुख युवा चेहरों में शामिल रहे हैं। राज्यसभा पहुंचने से पहले वे दिल्ली विधानसभा के सदस्य रहे और कई वित्तीय व प्रशासनिक मुद्दों पर मुखर रहे। अप्रैल 2022 में राज्यसभा सदस्य बनने के बाद वे राष्ट्रीय राजनीति में

पार्टी की अहम आवाज बने। अब उनकी जगह अशोक मित्तल को उपनेता बनाए जाने के प्रस्ताव के साथ पार्टी की संसदीय रणनीति में बदलाव का संकेत मिला है। पार्टी ने इस फैसले के पीछे औपचारिक कारण नहीं बताया है, लेकिन इसे संगठनात्मक संतुलन और संसदीय नेतृत्व के पुनर्गठन से जोड़कर देखा जा रहा है।

संसद में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के उठाए गए मुख्य मुद्दे

गिग वर्कर्स का मुद्दा: ब्लिंकिट, जोमैटो और स्विगी जैसे डिलीवरी पार्टनर्स के कम वेतन, 10-मिनट डिलीवरी मॉडल और सामाजिक सुरक्षा की कमी। *डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स:* कॉपीराइट एक्ट 1957 में संशोधन की मांग की, ताकि शिक्षकों और इन्फ्लुएंसर्स को एल्गोरिदम और गलत 'टेकडाउन' से बचाया जा सके। *खाद्य मिलावट:* राज्यसभा में यूरिया और अन्य मिलावटों का मुद्दा उठाया। *एयरपोर्ट पर सस्ता खाना:* यात्रियों को सस्ता खाना मिले, इसके लिए सभी 150+ एयरपोर्ट्स के डिपार्चर एरिया में किफायती कैफे की मांग की। 28-दिन का रीचार्ज: मोबाइल रीचार्ज 28 दिन के बजाय पूरे कैलेंडर महीने (30 या 31) का हो, बचा हुआ डेटा अगले महीने जुड़ जाए। *बैंक पेनल्टी:* मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगने वाले जुर्माने को पूरी तरह खत्म करने का प्रस्ताव दिया। *संयुक्त इनकम टैक्स फाइलिंग:* विवाहित जोड़ों के लिए एक साथ इनकम टैक्स फाइलिंग का विकल्प दिया जाए।

छात्रों के लिए बेहतर भविष्य के द्वार खोल रहा है सुभारती विश्वविद्यालयः डॉ. रविंद्र यादव

डॉ० रविंद्र प्रताप यादव
(प्रशासनिक अधिकारी एवं एडमिशन कॉर्डिनेटर)
रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय, देहरादून

वर्ष 2016 में जब रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय, देहरादून की स्थापना हुई थी तभी यह तय कर लिया गया था कि हमारा विश्वविद्यालय केवल डिग्री बांटने वाला संस्थान नहीं होगा बल्कि अपने विद्यार्थियों को रोजगारपरक पाठयक्रम उपलब्ध कराने वाले संस्थान के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। चूंकि सुभारती शिक्षा को केवल डिग्री नहीं बल्कि जीवन संवारने का एक सशक्त माध्यम मानता है इसलिए हमारा लक्ष्य शुरू से ही साफ था कि कि हम अपने विद्यार्थियों में शिक्षा, सेवा और संस्कार के भावना से शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान एवं रोजगारपरक पाठ्यक्रमों के माध्यम से सर्वांगीण विकास और उनके बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। आज हमारे कॉलेज में पढ़ने वाला हर विद्यार्थी अपने बेहतर भविष्य को लेकर आश्वस्त है। आज सुभारती विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों को अनुभवी एवं विशेषज्ञ फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम, अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, क्लिनिकल रिसर्च सुविधाएं, लाइब्रेरी, हॉस्टल और स्पोर्टस जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। हमारे कॉलेज की फैकल्टी पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपने विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में लगी हुई है। विश्वविद्यालय अपने होनहार और मेहनती छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में भी उनको प्रोत्साहित करता है। विद्यार्थियों को सही गाईडेंस के लिए हमारे सारे टीचर हर समय तैयार रहते है और प्लेसमेंट में हमारा पूरा संस्थान उनकी पूरी मदद करता है। आज हमारे विश्वविद्यालय में कई तरह के रोजगारपरक पाठ्यक्रम संचालित हो रहे है जिनमें प्रमुख रूप से एम०बी०बी०एस०, नर्सिंग (बी.एस.सी. एवं जी.एन.एम.), पैरामेडिकल-फिजियोथेरेपी, फार्मेसी (बी.फार्म. और डी.फार्मा), योगा एवं नैचुरोपैथी, होटल मैनेजमेन्ट- (बी.एच.एम. और डी.एच.एम), फाइन आर्टस और फैशन डिजानिंग, बी.सी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम एवं मैनेजमेन्ट, बी.ए, बुद्धिस्ट, बी.एड, जर्नलिज्म एवं मास कम्यूनिकेशन, पी.एच.डी आदि प्रमुख है। हमारे कई रोजगारपरक कोर्सेस ऐसे है जिनमें सीटे सीमित होती है और वे जल्दी ही फुल हो जाते है। सुभारती विश्वविद्यालय अपने बढ़ते हुए विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए अब नये भवनों (क्लासरूम/हॉस्टल/एडमिन ब्लॉक आदि) का भी निर्माण कार्य करवा रहा है। जब छात्र सुभारती विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता है तब उसके सुरक्षित भविष्य की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है और छात्र को होने वाली किसी भी समस्या के समाधान के लिए लिए मेरा ऑफिस हर समय उपलब्ध रहता है। अगर आप देहरादून में कोई विश्वसनीय विश्वविद्यालय की तलाश में है तो आपकी तलाश सुभारती विश्वविद्यालय पर आकर समाप्त हो जाती है।

पश्चिम बंगाल में बढ़ती अराजकता: — लोकतंत्र के लिए चुनौती —

ललित गर्ग

पश्चिम बंगाल, जो कभी सांस्कृतिक चेतना, बौद्धिकता और राजनीतिक परिपक्वता का प्रतीक माना जाता था, आज एक ऐसे संक्रमणकाल से गुजर रहा है, जहां लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ें लगातार कमजोर होती प्रतीत हो रही हैं। जैसे-जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे-वैसे राज्य में हिंसा, अराजकता अलोकतांत्रिकता और राजनीतिक असहिष्णुता की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यह केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति घटते सम्मान और कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति का भी द्योतक है। हाल ही में मालदा जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण अर्थात एसएआर को लेकर जिस प्रकार का असंतोष और तनाव देखने को मिला, वह भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति अविश्वास को दर्शाता है। मतदाता सूची में नाम जुड़ना या हटना एक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके लिए स्पष्ट नियम और प्रावधान होते हैं। यदि इस प्रक्रिया को राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा या प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाया जाएगा, तो निष्पक्ष चुनाव की पूरी प्रक्रिया ही संदिग्ध हो जाएगी। एसएआर प्रक्रिया में बाधक बनते हुए जिसे तरह से न्यायिक अधिकारियों को नौ घंटे तक बंधक बनाए जाने की घटना सामने आयी है, वह न केवल चिंताजनक है बल्कि लोकतंत्र के लिये एक गंभीर चेतावनी भी है। यह उस व्यापक घातक एवं विडम्बनापूर्ण प्रवृत्ति का हिस्सा है, जिसमें प्रशासनिक और न्यायिक तंत्र को भी राजनीतिक दबाव और भीड़तंत्र के आगे झुकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। विशेष रूप से यह तथ्य कि बंधक बनाए गए अधिकारियों में महिलाएं भी शामिल थीं, इस घटना को और अधिक गंभीर बना देता है। यह न केवल कानून के शासन पर प्रश्नचिह्न लगाता है, बल्कि समाज में बढ़ती असंवेदनशीलता को भी उजागर करता है।

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास नया नहीं है। 1960 और 70 के दशक में नक्सल आंदोलन के दौरान हिंसा का जो दौर शुरू हुआ था, उसने राज्य की राजनीतिक संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। इसके बाद वामपंथी शासन के लंबे कालखंड में भी राजनीतिक विरोधियों के प्रति असहिष्णुता और हिंसा की घटनाएं समय-समय पर सामने आती रहीं। सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस एवं ममता बनर्जी के शासन में यह प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई, बल्कि नए स्वरूप में सामने आई। यह स्पष्ट संकेत है कि समस्या केवल किसी एक दल या विचारधारा की नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र में व्याप्त एक गहरे संकट की है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, चुनावों के निकट आते ही जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, वे लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे का संकेत देती हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसे संवेदनशील कार्य में लगे अधिकारियों को बंधक बनाना यह दर्शाता है कि कुछ तत्व चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि मतदाता की स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव के अधिकार पर सीधा हमला है।

इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता उल्लेखनीय है। समय-समय पर न्यायालय ने राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी की याद दिलाई है। किंतु यह भी एक चिंताजनक तथ्य है कि इन निर्देशों का जमीनी स्तर पर अपेक्षित प्रभाव नहीं दिखाई देता। इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या राज्य प्रशासन एवं सत्तारूढ पार्टी इन निर्देशों को लागू करने में अक्षम है या इच्छुक नहीं है? यदि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश भी प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी है। चुनाव के समय बढ़ती अराजकता के पीछे राजनीतिक बौखलाहट भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकती है। जब किसी दल को अपनी लोकप्रियता में गिरावट का भय होता है, तो वह अक्सर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को दरकिनार कर असंवैधानिक उपायों का सहारा लेने लगता है। पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसी ही प्रवृत्तियां देखने को मिल रही हैं, जहां सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं पर विपक्ष को डराने, प्रशासनिक कार्यों में बाधा डालने और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगते रहे हैं। यदि इन आरोपों में सच्चाई है, तो यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत है।

नागरिक समाज सक्रिय रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आगे नहीं आएगा, तब तक केवल प्रशासनिक उपायों से इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें कानून का शासन, संस्थाओं की स्वतंत्रता और नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति इन सभी पहलुओं पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। यदि चुनाव प्रक्रिया ही निष्पक्ष और शांतिपूर्ण नहीं रह जाती, तो लोकतंत्र का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति मतदाता का विश्वास होता है, और यदि मतदाता को यह लगने लगे कि मतदाता सूची, चुनाव प्रक्रिया या प्रशासन

किसी राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है, तो लोकतंत्र की विश्वसनीयता स्वत: कमजोर होने लगती है। इस पूरे घटनाक्रम में प्रशासनिक नाकामी का प्रश्न भी गंभीरता से सामने आता है। किसी भी राज्य में यदि अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं, न्यायिक अधिकारी तक बंधक बना लिए जाते हैं और पुलिस या प्रशासन समय पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाता, तो यह प्रशासनिक तंत्र की कमजोरी का स्पष्ट प्रमाण है। प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखना और सरकारी कार्यों को निर्भय वातावरण में संपन्न कराना होता है। यदि प्रशासन यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है, तो इससे जनता में भय और अविश्वास दोनों बढ़ते हैं। जनता का विश्वास ही किसी सरकार की सबसे बड़ी पूंजी होता है, और जब यही विश्वास डगमगाने लगता है, तो शासन की वैधता पर भी प्रश्नचिह्न लगने लगते हैं।

राजनीतिक दलों की भूमिका भी इस पूरे परिदृश्य में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों के संवाहक भी होते हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यकर्ताओं को संयम, कानून के सम्मान और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करें। लेकिन जब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कटु संघर्ष में बदल जाती है और कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह से राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक दल चुनाव को युद्ध नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक उत्सव के रूप में देखें। आज आवश्यकता इस बात की है कि पश्चिम बंगाल की घटनाओं को केवल एक राज्य की समस्या न मानकर लोकतंत्र के लिए चेतावनी के रूप में देखा जाए। यदि प्रशासनिक तंत्र कमजोर होगा, राजनीतिक दल मर्यादा नहीं रखेंगे, और जनता का विश्वास कम होता जाएगा, तो लोकतंत्र केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा। लोकतंत्र की रक्षा केवल संविधान या न्यायालय नहीं कर सकते, इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक निष्पक्षता और जनता की जागरूकताकृतीनों का संतुलन आवश्यक है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान परिस्थितियां हमें यही संदेश देती हैं कि लोकतंत्र को केवल चुनाव से नहीं, बल्कि व्यवस्था की निष्पक्षता, कानून के शासन और नागरिक विश्वास से मजबूत बनाया जा सकता है।

इस परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है कि राज्य सरकार, चुनाव आयोग और न्यायपालिका मिलकर ठोस कदम उठाएं। कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाए, दोषियों के खिलाफ त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई हो और प्रशासनिक तंत्र को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखा जाए। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को भी आत्ममंथन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कार्यकर्ता लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करें। निश्चित ही यह समझना होगा कि लोकतंत्र की रक्षा केवल संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति एक चेतावनी है कि यदि समय रहते सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो यह अराजकता और गहराई तक फैल सकती है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है कि हम सभी मिलकर कानून, नैतिकता और सहिष्णुता के मूल्यों को पुन: स्थापित करें। पश्चिम बंगाल आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां से वह या तो लोकतांत्रिक पुनर्जागरण की ओर बढ़ सकता है या अराजकता के गहरे गर्त में गिर सकता है। यह निर्णय न केवल राजनीतिक नेतृत्व, बल्कि पूरे समाज को मिलकर लेना होगा।

एक कहानी थाली और टैबलेट की

डाइटिशियन वंदना,
फूड सप्लीमेंट एडवाइजर
न्यूट्रीबीट्ज वेलनेस स्टूडियो

जब सेहत टैबलेट में ढूंढी जाने लगी....

सुबह के 8 बजे थे। ऋतु अपनी रसोई में खड़ी थी-एक हाथ में चाय का कप, और दूसरे हाथ में 4 अलग-अलग डिब्बे। कैल्शियम, विटामिन डी, मल्टी-विटामिन, और एक "एनर्जी बूस्टर" कैप्सूल। उसने जल्दी से सब गोलियां पानी के साथ निगल ली और फिर बिना नाश्ता किए ऑफिस के लिए निकल गई।

क्या यह दृश्य आपको जाना-पहचाना लगता है? आजकल हम सब ने सेहत को टैबलेट में ढूंढना शुरू कर दिया है। हमें लगता है कि एक कैप्सूल हमारी थकान मिटा देगा, एक टैबलेट हमारी इम्युनिटी बढ़ा देगी। लेकिन कहीं न कहीं, इस दौड़ में हम एक बहुत बुनियादी बात भूल गए हैं-

"खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को जीवन देने के लिए होता है।"

जब हम एक ताजा फल या सब्जी खाते हैं, तो हम सिर्फ विटामिन नहीं लेते....

हम लेते हैं जीवित ऊर्जा, फाइटोकेमिकल्स, एंजाइम्स और प्रकृति का एक सम्पूर्ण उपहार। ये वही तत्व हैं जो किसी भी टैबलेट में पूरी तरह से नहीं आ सकते।

एक संतरा और एक टैबलेट की कहानी सोचिए....

आपके सामने दो चीजें रखी हैं, एक तरफ एक चमकता हुआ संतरा और दूसरी तरफ एक विटामिन सी की टैबलेट। दोनों का लेबल कहता है- "विटामिन सी", विज्ञान भी कहता है-दोनों में एस्कॉर्बिक एसिड है। तो फिर फर्क क्या है? फर्क है "जिंदगी" का।

संतरा सिर्फ विटामिन सी नहीं है....

उसमें वो सारे अदृश्य तत्व होते हैं जो शरीर को सही तरीके से उस विटामिन को अवशोषित करने में मदद करते हैं। इसे कहते हैं-पोषक तत्वों का साथ मिलकर काम करना, यानी न्यूट्रिएंट सिनर्जी। जैसे एक टीम मिलकर मैच जीतती है, वैसे ही पोषक तत्व भी मिलकर शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। विटामिन बी अकेला कमजोर होता है, लेकिन बी-कॉम्प्लेक्स शक्तिशाली होता है। कैल्शियम अकेला अधूरा है, विटामिन डी और मैग्नीशियम के साथ ही मजबूत बनता है।

लेकिन जब हम सिर्फ एक ही सप्लीमेंट लेते हैं, तो यह वैसा ही है जैसे एक खिलाड़ी से पूरा मैच जीतने की उम्मीद करना।

सच्चाई जो हर किसी को जाननी चाहिए।

एक दिन ऋतु मेरे क्लिनिक आई, थकी हुई, ऊर्जा की कमी से जूझती हुई और उलझन में। उसने कहा: "मैम, मैं इतने सप्लीमेंट्स लेती हूं, फिर भी मुझे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा?" मैंने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा:

"आप अपनी थाली में क्या लेती हैं?" बस वहीं से उसकी यात्रा बदल गई। धीरे-धीरे उसने अपनी डाइट में मौसमी फल, घर का बना खाना, ताजी सब्जियां और संतुलित आहार शामिल किया। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया। ऊर्जा बढ़ रही है, पाचन सुधर रहा है, मन हल्का और ताजा लग रहा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा-

"मैम, लगता है मेरी रसोई ही मेरी दवा की दुकान है...."

अंतिम संदेश- वापस थाली की ओर

यह लेख सप्लीमेंट्स के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनके सही उपयोग के लिए है। कुछ परिस्थितियों में सप्लीमेंट्स जरूरी होते हैं- जैसे खून की कमी की स्थिति, गर्भावस्था या किसी विशेष रोग में। लेकिन बिना समझ के उनका उपयोग करना शरीर के लिए लाभकारी नहीं होता। अगर हम हर समस्या का समाधान टैबलेट में ढूंढेंगे, तो हम अपने शरीर की असली जरूरत को नजरअंदाज कर देंगे। तो आज एक छोटा सा कदम उठाइए- अपनी थाली को रंग-बिरंगी, प्राकृतिक और पोषक बनाइए। क्योंकि सच्चाई यह है-

"जब थाली सही हो जाती है, तो दवा की जरूरत धीरे-धीरे कम हो जाती है।"

अफगानिस्तान से लेकर भारत तक भूकंप के झटके!

डॉ श्रीगोपाल नारसन एडवोकेट

भारत मे दिल्ली-एनसीआर सहित समूचे उत्तर भारत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके के आने पर लोग घरों से बाहर निकल गए। ये झटके दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा राजस्थानऔर पंजाब सहित कई प्रदेशों में महसूस किए गए हैं। इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में बताया जा रहा है। दिल्ली-एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस होने से लोग दहशत में आ गए। गनीमत रही कि भूकंप से कहीं जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान-ताजिकिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में बताया जा रहा है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.9 मापी गई है। भूकंप के झटके जम्मू-कश्मीर के उधमपुर, पुंछ और कश्मीर घाटी के कई इलाकों में महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान-ताजिकिस्तान सीमा क्षेत्र में जमीन के अंदर 175 किलोमीटर नीचे था। भूकंप का केंद्र जमीन के काफी अंदर होने की वजह से इसका असर कम हुआ है। अफगानिस्तान-ताजिकिस्तान सहित उत्तर भारत में भूंकप आने से पहले तिब्बत में धरती हिली थी। तिब्बत में बीती रात करीब 8.12 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तिब्बत में आए भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई थी। पिछले साल म्यांमार और थाईलैंड में दोपहर के समय आए भयंकर भूकंप को रिक्टर पैमान पर 7.9 की तीव्रता का नापा गया था। इतने तेज भूकंप के कारण दोनों ही देशों में भारी तबाही हुई थी। इन देशों की विशाल इमारतें और पुल ढह गए और भारी जान माल का नुकसान हुआ था। थाईलैंड के प्रधानमंत्री शिनवात्रा ने बैंकाक के अंदर आपातकाल की घोषणा की थी। इस भूकंप का केंद्र म्यांमार बताया गया था। जिसका भारी प्रभाव थाईलैंड तक पड़ा था। बैंकॉक में 7.9 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से इमारतें हिलने लगीं थी। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और जर्मनी के जीएफजेड भूविज्ञान केंद्र ने बताया कि दोपहर को यह भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था, जिसका केंद्र म्यांमार में था। ग्रेटर बैंकॉक क्षेत्र की आबादी 170 लाख से अधिक है, जिनमें से कई लोग ऊंची इमारतों वाले अपार्टमेंट में रहते हैं। दोपहर करीब डेढ़ बजे भूकंप आने पर इमारतों में अलार्म बजने लगे और घनी आबादी वाले मध्य बैंकॉक की ऊंची इमारतों एवं होटल से लोगों को बाहर निकाला गया। भूकंप इतना शक्तिशाली था कि कुछ ऊंची इमारतों के अंदरूनी हिस्सों में 'स्वीमिंग पूल' में पानी में लहरें उठती दिखीं। भूकंप का केंद्र मध्य म्यांमार में था, जो मोनीवा शहर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए जहां सैंकड़ो लोग इमारतों से बाहर निकल आए। हालांकि जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज ने बताया कि म्यांमार में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र मंडाले शहर के पास 10 किमी की गहराई पर था। म्यांमार दुनिया के सबसे भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक माना जाता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड राज्यों में आज आए भूकंप से लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए। वही दिल्ली व उसके आसपास के क्षेत्र में विगत वर्ष 17 फरवरी की सुबह भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए थे, जिसमे कई सेकंड तक धरती डोलती रही थी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई थी, इसका केंद्र दिल्ली के पास ही धरती से 5 किलोमीटर की गहराई में था। इसीलिए तेज झटके महसूस हुए। कुछ सेकंड तक चलने वाले भूकंप के झटके इतने तेज थे कि इमारतों के अंदर जोरदार कंपन महसूस हुआ। भूकंप सुबह 5 बजकर 36 मिनट पर आया था, जिससे लोगों की नींद उड़ गई थी। भूकंप के झटके दिल्ली-एनसीआर भूकंपीय क्षेत्र 4 में आते है, जिससे यहां मध्यम से तीव्र भूकंप आने का खतरा रहता है। समय-समय पर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं, लेकिन इस तीव्रता के झटके बहुत समय बाद महसूस किए गए हैं। उत्तराखंड

समेत नेपाल और भारत के अन्य क्षेत्रों में धरती बार बार डोलने लगती है। भूकंप के तेज झटकों से लोग दहशत में आ जाते है। सन 2022 में आए भूकंप के झटके इतने तेज थे कि गहरी नींद में सोए लोग हड़बड़ाहट में उठे और घरों से बाहर की ओर भागे थे।उस समय उत्तराखंड में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.5 मापी गई थी। दिल्ली के साथ ही नोएडा और गुरुग्राम में भी कई सेकेंड तक भीषण झटके महसूस किए गए। इसके कारण लोग उठ गए और कई लोग अपनी सोसायटी में बाहर निकल आए।ऐसा लगा कि बेड को कोई बहुत तेज धक्का मार रहा है। इस दौरान घर के फैन और झूमर भी भूकंप के असर के कारण तेजी से हिलने लगे। भूकंप पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। यह पृथ्वी के स्थलमण्डल में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकम्पीय तरंगों की वजह से होता है। भूकम्प बहुत हिंसात्मक हो सकते हैं और कुछ ही क्षणों में लोगों को गिराकर चोट पहुँचाने से लेकर पूरी आबादी को ध्वस्त कर सकने की इसमें क्षमता होती है। भूकंप का मापन भूकम्पमापी यंत्र से किया जाता है, जिसे सीस्मोग्राफ कहते है। 3 या उस से कम रिक्टर परिमाण की तीव्रता का भूकंप अक्सर अगोचर होता है, जबकि 7 रिक्टर की तीव्रता का भूकंप बड़े क्षेत्रों में गंभीर क्षति का कारण बन जाता है। भूकंप के झटकों की तीव्रता का मापन मरकैली पैमाने पर किया जाता है। पृथ्वी की सतह पर, भूकंप अपने आप को, भूमि को हिलाकर या विस्थापित कर के प्रकट करता है। जब एक बड़ा भूकंप उपरिकेंद्र अपतटीय स्थिति में होता है, यह समुद्र के किनारे पर पर्याप्त मात्रा में विस्थापन का कारण बनता है। भूकंप के झटके कभी-कभी भूस्खलन और ज्वालामुखी को भी पैदा कर सकते हैं। भूकंप अक्सर भूगर्भीय दोषों के कारण आते हैं। (लेखक सामाजिक चिंतक व वरिष्ठ साहित्यकार है)

सीएम धामी ने 14 दायित्वधारियों को दी बोर्ड-निगमों में जिम्मेदारी

मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब संगठनात्मक और राजनीतिक संतुलन साधने की दिशा में दायित्वों का बंटवारा शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने बोर्ड, निगम और परिषदों के खाली पदों पर 14 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपते हुए विभिन्न समितियों में उपाध्यक्ष और अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार वरिष्ठ नेताओं के साथ ही क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए नियुक्तियां की गई हैं। इनमें नैनीताल के वरिष्ठ पत्रकार ध्रुव रौतेला सहित कई नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है, जिससे संगठन और सरकार के बीच समन्वय मजबूत करने की कोशिश मानी जा रही है। दिव्य हिमगिरि रिपोर्ट।

मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संगठनात्मक और राजनीतिक संतुलन साधने की दिशा में दायित्वों का बंटवारा शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने बोर्ड, निगम और परिषदों के खाली पदों पर 14 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपते हुए विभिन्न समितियों और आयोगों में उपाध्यक्ष व अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। सरकार की ओर से जारी आदेशों में क्षेत्रीय संतुलन, संगठन में सक्रिय रहे नेताओं को जिम्मेदारी और विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की रणनीति साफ दिखाई दे रही है। इन नियुक्तियों को आगामी राजनीतिक गतिविधियों और संगठनात्मक मजबूती से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जारी आदेशों के अनुसार नैनीताल के वरिष्ठ पत्रकार ध्रुव रौतेला को मीडिया सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं टिहरी की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाण को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए जड़ी-बूटी सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। काशीपुर की पूर्व प्रदेश मंत्री सीमा चौहान को मत्स्य विकास अभिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में अल्मोड़ा के गोविंद सिंह को हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि चम्पावत के मुकेश महराना को चाय विकास सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कुलदीप बुटोला को उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता खेम सिंह चौहान को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा चारु कोठारी को राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है। भाजपा नेता बलजीत सोनी को अल्पसंख्यक आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चम्पावत की हरिप्रिया जोशी को राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। प्रेम सिंह राणा को जनजाति आयोग में उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि अशोक वर्मा को राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। धामी सरकार की ओर से किए गए इस दायित्व बंटवारे में अलग-अलग जिलों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। पहाड़ और मैदानी क्षेत्रों के नेताओं को शामिल करते हुए संगठन के सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि लंबे समय से दायित्वों की प्रतीक्षा कर रहे नेताओं को समायोजित कर सरकार ने संगठन में संतुलन साधने का प्रयास किया है।

धामी सरकार का संगठनात्मक संतुलन के साथ राजनीतिक संदेश

मंत्रिमंडल विस्तार के बाद किए गए इस दायित्व बंटवारे को राजनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है। सरकार ने विभिन्न आयोगों और परिषदों में नियुक्तियां कर संगठन के वरिष्ठ और सक्रिय नेताओं को जिम्मेदारी दी है, जिससे कार्यकर्ताओं में संदेश गया है कि सरकार संगठन के साथ समन्वय बनाकर चल रही है। लंबे समय से बोर्ड और निगमों के पद खाली चल रहे थे, जिन्हें लेकर पार्टी के भीतर भी चर्चाएं चल रही थीं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब इन पदों पर नियुक्तियां कर सरकार ने असंतुष्ट नेताओं को साधने की कोशिश की है। खास बात यह है कि नियुक्तियों में क्षेत्रीय संतुलन के साथ सामाजिक समीकरणों का भी ध्यान रखा गया है। महिलाओं, पिछड़ा वर्ग, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े नेताओं को भी जिम्मेदारी देकर व्यापक प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है। धामी सरकार ने इन नियुक्तियों के जरिए संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। विभिन्न आयोगों और परिषदों में नियुक्त किए गए पदाधिकारी सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में भूमिका निभाएंगे। साथ ही आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों में भी इनकी सक्रिय भागीदारी रहेगी। माना जा रहा है कि यह दायित्व बंटवारा आगे भी जारी रह सकता है और शेष खाली पदों पर भी जल्द नियुक्तियां की जाएंगी। फिलहाल 14 नेताओं को जिम्मेदारी देकर धामी सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब संगठनात्मक समायोजन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सरकार की इस पहल को राजनीतिक संतुलन साधने और संगठन को मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

यूजेवीएन लिमिटेड के विद्युतगृहों द्वारा रिकॉर्ड विद्युत उत्पादन

उत्पादन की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2025-26 यूजेवीएन लिमिटेड के लिए बेहतरीन वर्ष साबित हुआ है। ज्ञातव्य है कि निगम की परियोजनाओं द्वारा नदी जल की उपलब्धता के अनुरूप ही उत्पादन किया जाता है तथा इस वर्ष परियोजनाओं के जल संग्रहण क्षेत्र में कम वर्षा एवं हिमपात के कारण अधिकांश समय नदियों का जलस्तर कम ही रहा है। इन विकट परिस्थितियों में भी निगम के अधिकांश विद्युत गृहों द्व ारा बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए वर्ष के अंत तक अपने तय विद्युत उत्पादन लक्ष्य को पार कर लिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए यूजेवीएन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अजय कुमार सिंह ने बताया कि योजनाबद्ध तरीके से रखरखाव एवं संचालन के परिणामस्वरूप मशीनों की उपलब्धता 90 प्रतिशत के आस-पास रही जो कि उत्पादन को बेहतरीन बनाने में सहयोगी रही। उन्होंने बताया कि वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं के साथ ही लघु जल विद्युत परियोजनाओं का भी इस रिकॉर्ड उत्पादन में सराहनीय योगदान रहा।

अजय कुमार सिंह ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में यूजेवीएन लिमिटेड के ढकरानी, ढालीपुर, कुल्हाल, तिलोथ, चीला, रामगंगा, व्यासी, गलोगी, दुनाव, उर्गम, कालीगंगा प्रथम एवं द्वितीय तथा मध्यमहेश्वर विद्युत गृहों द्वारा अपने वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु तय किए गए लक्ष्यों से अधिक विद्युत उत्पादन किया गया है।

प्रबंध निदेशक अजय कुमार सिंह ने निगम के विद्युत गृहों की इस उपलब्धि पर हर्ष प्रकट करते हुए कहा कि यूजेवीएन लिमिटेड के कुशल प्रबंधन, बेहतरीन कार्य योजना तथा उत्कृष्ट कार्यसंस्कृति से ही यह रिकार्ड उत्पादन संभव हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में निगम की लक्ष्य से अधिक उत्पादन करने वाले विद्युत गृहों का विवरण-

विद्युत गृह - लक्ष्य/उत्पादन

ढकरानी- 101 मिलियन यूनिट / 126.170 मिलियन यूनिट
ढालीपुर- 220 मिलियन यूनिट / 226.654 मिलियन यूनिट
कुल्हाल- 140 मिलियन यूनिट / 147.574 मिलियन यूनिट
व्यासी- 331 मिलियन यूनिट / 348.864 मिलियन यूनिट
तिलोथ- 467 मिलियन यूनिट / 482.355 मिलियन यूनिट
चीला- 616 मिलियन यूनिट / 645 मिलियन यूनिट
रामगंगा- 290 मिलियन यूनिट / 326.727 मिलियन यूनिट
खटीमा- 21.230 मिलियन यूनिट
गलोगी- 7 मिलियन यूनिट / 8.103 मिलियन यूनिट
दुनाव- 2.4 मिलियन यूनिट / 3.017 मिलियन यूनिट
उरगम- 7.1 मिलियन यूनिट / 7.665 मिलियन यूनिट
काली गंगा-प्रथम- 8 मिलियन यूनिट / 8.224 मिलियन यूनिट
काली गंगा-द्वितीय- 12 मिलियन यूनिट / 12.221 मिलियन यूनिट
मध्यमहेश्वर- 32 मिलियन यूनिट / 33.781 मिलियन यूनिट

डॉ. संदीप सिंघल की गरिमामय विदाई: यूजेवीएन लिमिटेड मुख्यालय 'उज्ज्वल' में विदाई समारोह संपन्न

यूजेवीएन लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक डॉ. संदीप सिंघल के सम्मान में निगम मुख्यालय 'उज्ज्वल' में एक गरिमामय विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने डॉ. सिंघल के साथ कार्यकाल के अपने अनुभवों और संस्मरण ों को साझा करते हुए उनके नेतृत्व, कार्यकुशलता एवं सौम्य व्यक्तित्व की सराहना की।

समारोह में डॉ. संदीप सिंघल ने भी अपने सेवाकाल के अनुभव साझा करते हुए निगम के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया तथा निगम की निरंतर प्रगति की कामना की।

इस अवसर पर यूजेवीएन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अजय कुमार सिंह, यूपीसीएल एवं पिटकुल के प्रबंध निदेशक जी.एस. बुदियाल, निदेशक परियोजनाएं सुरेश चन्द्र बलूनी, अधिशासी निदेशक सुधाकर बडोनी, आशीष कुमार जैन तथा विवेक आत्रेय सहित बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

जानिए कैसा होगा आपका यह सप्ताह

पं. दीपक प्रसाद, शास्त्री (मो. 9557730042)
(ज्योतिष, कर्मकाण्ड, धर्मिक अनुष्ठान आदि)

मेष राशि- विद्यार्थी सोशल मीडिया और फालतू बातों में पड़कर अपने करियर के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न करें। कोई भी समस्या आने पर उसके निवारण के लिए उसकी तह तक जाना जरूरी है। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिशियल कार्यप्रणाली में बदलाव आने से कुछ दिक्कतें रह सकती हैं। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेंगी। भाग्यशाली रंग- सफेद, भाग्यशाली अंक- 5

मिथुन राशि- धार्मिक अथवा आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय व्यतीत करने से आपको सुकून मिलेगा तथा व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। किसी-किसी समय थकान की वजह से कमजोरी महसूस करेंगे, परंतु आपकी कार्य क्षमता में कोई कमी नहीं आएगी। घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। प्रेम संबंधों में पारिवारिक स्वीकृति मिलेगी। भाग्यशाली रंग- नीला, भाग्यशाली अंक- 8

सिंह राशि- विद्यार्थियों को करियर से संबंधित कोई निर्णय लेने में अनुभवी लोगों का सहयोग मिलेगा। दूसरों के समक्ष अपनी योजनाओं और गतिविधियों का बखान न करें। अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखें। घर-परिवार में अनुशासित तथा शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। विवाहेत्तर प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर रखें। भाग्यशाली रंग- केसरिया, भाग्यशाली अंक- 6

तुला राशि- परिवार में सुख-शांति बनाए रखना आपकी प्राथमिकता रहेगी। दांपत्य संबंधों में मधुरता रहेगी। कोई यात्रा का प्रोग्राम भी बन सकता है। अत्यधिक मेहनत और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही आपको शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। एलर्जी अथवा मौसमी बीमारी के संकेत हैं। भाग्यशाली रंग- हरा, भाग्यशाली अंक- 6

धनु राशि- कुछ समय अपने स्वास्थ्य और व्यक्तित्व को निखारने में भी अवश्य लगाएं। व्यावसायिक भरोसेमंद पार्टियों द्वारा नए प्रस्ताव मिलेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। वैवाहिक संबंधों में चल रही गलतफहमी दूर होगी तथा संबंधों में मधुरता आएगी। लव पार्टनर के साथ मुलाकात का अवसर मिलेगा। भाग्यशाली रंग- पीला, भाग्यशाली अंक- 1

कुंभ राशि- मित्रों अथवा संबंधियों के साथ आपकी किसी गलती की वजह से संबंध खराब हो सकते हैं। परिवार तथा घर के बुजुर्गों को भी आपकी देखभाल की जरूरत है, इसलिए उनका भी ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में आपका मैनेजमेंट उचित तालमेल प्रोडक्शन को और अधिक बढ़ाएगा तथा कार्य क्षेत्र की व्यवस्था भी उचित रखेगा। भाग्यशाली रंग- मेहरून, भाग्यशाली अंक- 4

वृषभ राशि- युवा वर्ग अपने अंदर छिपी प्रतिभा को पहचानें और उसका उपयोग करें। इस समय बनाई गई योजनाएं निकट भविष्य में शुभ अवसर प्रदान करने वाली हैं। सरकारी विभाग से जुड़े लोगों के लिए दिन व्यस्त रहने वाला है। अपने व्यवहार में परिपक्वता लाएं। प्रेम संबंधों में अपना समय और पैसा व्यर्थ न करें। भाग्यशाली रंग- आसमानी, भाग्यशाली अंक- 7

कर्क राशि- पारिवारिक व्यवस्था को लेकर भी कुछ खास योजनाएं बनेंगी। अनावश्यक खर्चों की अधिकता से परेशान रहेंगे। अपने ऊपर अत्यधिक कार्यभार न लें। अपने व्यक्तिगत कार्यों को प्राथमिकता दें। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेने से राहत रहेगी। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतें। भाग्यशाली रंग- बादामी, भाग्यशाली अंक- 2

कन्या राशि- सामाजिक गतिविधियों के प्रति आपका योगदान आपको मानसिक सुकून प्रदान करेगा। आप अपनी किसी नकारात्मक आदत को छोड़ने का भी संकल्प करें। आपके मन में किसी के प्रति शक की भावना संबंधों को खराब कर सकती है। इसलिए समय के अनुसार अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना जरूरी है। भाग्यशाली रंग- आसमानी, भाग्यशाली अंक- 4

वृश्चिक राशि- आपकी किसी समस्या का निवारण होगा। कुछ समय रोचक और ज्ञानवर्धक साहित्य पढ़ने में जरूर बिताएं, इससे आपके व्यक्तित्व में आश्चर्यजनक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। विद्यार्थी ओवरकॉन्फिडेंस में अपनी पढ़ाई का सिस्टम बिगाड़ सकते हैं। वैवाहिक संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बनी रहेंगी। भाग्यशाली रंग- बादामी, भाग्यशाली अंक- 7

मकर राशि- इस समय कोई भी नया अवसर मिले, तो उसे तुरंत हासिल करने की कोशिश करें, फायदा ही होगा। अनावश्यक खर्चों पर काबू पाएं। किसी के साथ वाद-विवाद अथवा कहासुनी जैसी स्थिति न उत्पन्न होने दें। पति-पत्नी का एक-दूसरे के प्रति सहयोगात्मक व्यवहार घर को खुशनुमा बनाकर रखेगा। भाग्यशाली रंग- लाल, भाग्यशाली अंक- 9

मीन राशि- किसी नजदीकी संबंधी को लेकर आपके अंदर शक जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसकी वजह से संबंध भी खराब हो सकते हैं। अगर कार्य प्रणाली में कुछ परिवर्तन लाने की सोच रहे हैं, तो समय अनुकूल है। ऑफिस में अपने सहयोगी के साथ वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। भाग्यशाली रंग- क्रीम, भाग्यशाली अंक- 2

रणबीर कपूर की 'रामायण'

यश का रावण लुक बना सबसे बड़ा हाइलाइट

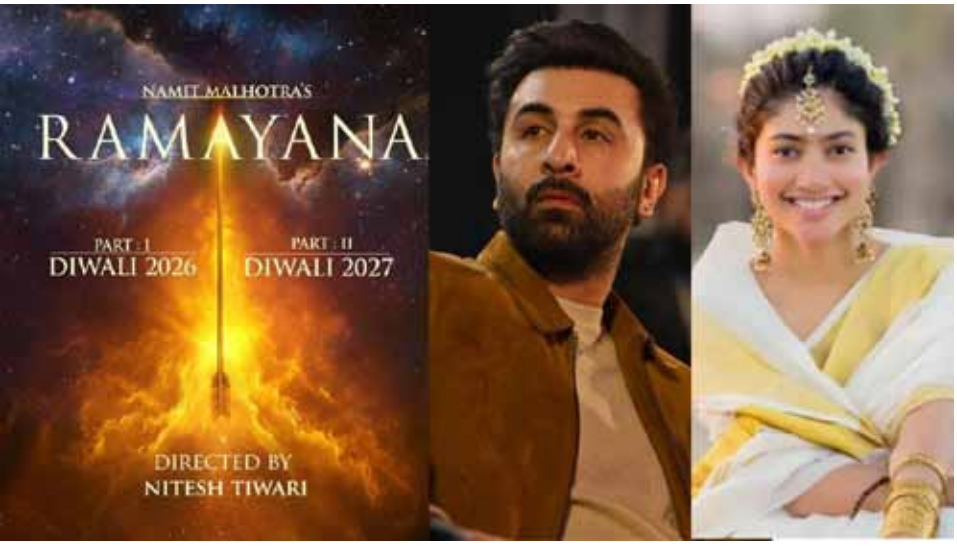

रणबीर कपूर की माइथोलॉजिकल फिल्म 'रामायण' का जब से फर्स्ट लुक सामने आया है, तब से ही फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच चुकी है। अब फैंस को इस फिल्म से सनी देओल और साई पल्लवी के लुक का बेसब्री से इंतजार है।

हालांकि, फैंस जिस स्टार के लुक के लिए सबसे ज्यादा बेताब हैं, वे हैं साउथ सुपरस्टार यश, जो फिल्म में 'रावण' की अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब हाल ही में रणबीर कपूर ने यश के लुक और किरदार को लेकर जो खुलासा किया है, उसे सुनकर फैंस की यह एक्साइटमेंट दोगुनी होने वाली है।

रणबीर कपूर ने हाल ही में यश के औरा की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, 'यश का स्टारडम जबरदस्त है और रावण का किरदार निभाने के लिए उसी तरह के औरा और स्क्रीन प्रेजेंस की जरूरत होती है। उनका रावण अब तक हमने जो देखा है, उससे काफी अलग है। मुझे लगता है कि दर्शकों को बड़े पर्दे पर यह नया रूप देखने में बहुत मजा आने वाला है।'

उन्होंने यश की सराहना करते हुए यह भी कहा कि दशानन जैसा शक्तिशाली किरदार निभाने के लिए सिर्फ अभिनय काफी नहीं है, उसके लिए आपको मजबूत स्टारडम और प्रभावशाली व्यक्तित्व की जरूरत होती है, जो यश के पास भरपूर है।

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण' को मेकर्स दो भागों में रिलीज कर रहे हैं। फिल्म का पहला पार्ट इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाला है, जिसकी आधिकारिक तारीख भी आ चुकी है। यह फिल्म 8 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इसके अलावा, रणबीर कपूर और यश की इस फिल्म का दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में रिलीज किया जाएगा।

इस ग्रैंड फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, सनी देओल और यश के अलावा अरुण गोविल, लारा दत्ता और रकुल प्रीत सिंह सहित कई बड़े सितारे अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे।

महाकाव्य 'रामायण' की गाथा काफी लंबी है, जिसे सिर्फ दो पार्ट्स में समेटना नामुमकिन सा लगता है। हालांकि, तीन पार्ट्स की योजना को दो में क्यों बदला गया, इसकी वजह बताते हुए नितेश तिवारी ने कहा, 'रामायण' महाकाव्य काफी विशाल है, इसलिए शुरुआत में हमने इसे तीन पार्ट्स में बनाने के बारे में सोचा था। वास्तव में इसका स्क्रीनप्ले भी तीन पार्ट्स के हिसाब से ही लिखा गया था। लेकिन फिर हमें लगा कि तीन पार्ट्स में फिल्म को बनाने में ज्यादा वक्त लगेगा और दर्शकों को इसके लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। यही बात सोचकर हमने फिल्म को तीन पार्ट्स के बजाय किसी तरह दो पार्ट्स में समेटने का फैसला किया।

डायरेक्टर ने कहा, मुझे लगता है कि इस समय हम एक बहुत अच्छे मुकाम पर हैं। इस फिल्म में हमने तय समय के भीतर वह सब कह दिया है, जो हम कहना चाहते थे और मुझे लगता है कि यह एक ऐसा फैसला है जिससे हम काफी संतुष्ट हैं। फिलहाल इसके दूसरे पार्ट की शूटिंग जारी है, उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी।

आपको बता दें कि नितेश तिवारी निर्देशित फिल्म 'रामायण' से प्रभु श्रीराम का लुक जारी हो चुका है। 'राम' की भूमिका रणबीर कपूर निभा रहे हैं। वहीं, माता सीता की भूमिका में साई पल्लवी होंगी, जबकि 'महाबली हनुमान' की भूमिका में सनी देओल नजर आएंगे। आगामी दिनों में इन सितारों के लुक्स भी जारी किए जाएंगे। 'रामायण' का पहला पार्ट इस साल दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज होगा।

EXPERIENCE HELI TOUR WITH

Himgiri Aviation & Tourism

SINCE 2018

3N/4D TOUR

A Unit of दिव्य हिमगिरि

केदार-बद्री यात्रा

BY HELICOPTOR

OPENING DATES

KEDARNATH	BADRINATH
22 April, 2026	23 April, 2026

ADVANCE BOOKING STARTS BOOK NOW

R.N.I.: UTTHIN/2010/41629 | Postal Regd. UA/DO/DDN/01/2025-2027

Contact for Reservation 8433456398, 9410353164

Email: himgiritourism@gmail.com

6 Municipal Road, Opp. Oxford School of Excellence, Dalanwala, Dehradun-248001 (UK)